

>

Title: Secretary-General laid a copy of the President's Address to both the Houses of Parliamentary assembled together on 31st January, 2020.

माननीय अध्यक्ष : महासचिव।

महासचिव : मैं राष्ट्रपति जी द्वारा 31 जनवरी, 2020 को एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों के समक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखती हूँ।

*माननीय सदस्यगण, 21वीं सदी के तीसरे दशक के प्रारंभ में, संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। मैं पुनः नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ, सभी संसद सदस्यों को इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी होने के लिए बधाई देता हूँ।

यह दशक भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस दशक में, हमारी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होंगे। इस दशक में, हम सभी को मिलकर नई ऊर्जा के साथ नए भारत के निर्माण को गति देनी है। मेरी सरकार के प्रयासों से पिछले पाँच वर्षों में इस दशक को भारत का दशक और इस सदी को भारत की सदी बनाने की मजबूत नींव रखी जा चुकी है।

चाहे पूज्य बापू का ग्राम स्वराज का सपना हो, बाबासाहब आंबेडकर की सामाजिक न्याय की नीति हो, नेहरू जी का आधुनिक भारत बनाने का स्वप्न हो, सरदार पटेल का एक भारत-श्रेष्ठ भारत का संकल्प हो, दीन दयाल उपाध्याय का अंत्योदय का लक्ष्य हो या लोहिया जी का समता समाज का दर्शन हो, हम भारत के लोग मिलकर इन सपनों को पूरा करेंगे।

माननीय सदस्यगण, भारत का संविधान, इन सपनों को पूरा करने में हम सभी का मार्गदर्शक है। कुछ सप्ताह पहले ही, 26 नवंबर को संविधान के 70 वर्ष पूरे हुए हैं। उस दिन देश के 12 करोड़ नागरिकों ने, सार्वजनिक रूप से संविधान की उद्देशिका को पढ़कर संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का संकल्प लिया।

हमारा संविधान देश के प्रत्येक नागरिक के अधिकारों की रक्षा के साथ ही, देश के नागरिकों को उनके कर्तव्यों का बोध भी कराता है। हमारा संविधान, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से हुए निर्णयों को देशवासियों द्वारा स्वीकार किये जाने की अपेक्षा भी रखता है। इसके साथ ही हमारा संविधान, इस संसद से तथा इस सदन में उपस्थित प्रत्येक सदस्य से राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए देशवासियों की आशाओं-आकांक्षाओं की पूर्ति करने और उनके लिए आवश्यक कानून बनाने की अपेक्षा भी रखता है।

माननीय सदस्यगण, मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 7 महीनों में संसद ने काम करने के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इस लोकसभा के पहले सत्र में, सदन द्वारा कार्य निष्पादन, पिछले सात दशकों में एक नया रिकॉर्ड रहा है।

मेरी सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति के कारण मुस्लिम महिलाओं को न्याय और अधिकार देने वाला तीन तलाक विरोधी कानून, देशवासियों को नए अधिकार देने वाला उपभोक्ता संरक्षण कानून, गरीबों की बचत की रक्षा करने वाला अनियमित जमा योजना प्रतिबंध कानून, गरीबों को चिटफंड स्कीमों के धोखे से बचाने वाला चिटफंड संशोधन कानून, बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों की सज़ा सख्त करने वाला कानून, सड़क हादसों में कमी लाने के लिए मोटर वाहन संशोधन कानून और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों को संरक्षण देने वाला कानून, जैसे अनेक ऐतिहासिक कानून बनाए गए हैं।

संविधान द्वारा अपेक्षित इस दायित्व को निभाने के लिए, मैं संसद के हरेक सदस्य का अभिनंदन करता हूँ।

माननीय सदस्यगण, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर देश की जनता द्वारा प्रकट किया जाने वाला विश्वास, हमारे लोकतंत्र की नींव को मजबूत करता

है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा रामजन्मभूमि पर फैसले के बाद देशवासियों द्वारा जिस तरह परिपक्वता से व्यवहार किया गया, वह भी प्रशंसनीय है। मेरी सरकार का स्पष्ट मत है कि पारस्परिक चर्चा-परिचर्चा तथा वाद-विवाद लोकतंत्र को और सशक्त बनाते हैं। वहीं विरोध के नाम पर किसी भी तरह की हिंसा, समाज और देश को कमजोर करती है।

माननीय सदस्यगण, लोकतंत्र में सबसे पवित्र होता है लोगों से मिला जनादेश। देश की जनता ने मेरी सरकार को ये जनादेश, नए भारत के निर्माण के लिए दिया है।

- एक ऐसा नया भारत, जिसमें हमारी पुरातन संस्कृति का गौरव हो और जो 21वीं सदी के विश्व को अपने ज्ञान की शक्ति से समृद्ध करे।
- एक ऐसा नया भारत, जिसमें पुरानी समस्याओं के समाधान के साथ ही विकास के नए अध्याय लिखे जाएं।
- एक ऐसा नया भारत, जिसमें गरीबों, दलितों, महिलाओं, युवाओं, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों को पर्याप्त सुविधा मिले और आगे बढ़ने के नए अवसर भी।
- एक ऐसा नया भारत, जिसका हर क्षेत्र विकास करे, कोई क्षेत्र पिछड़ा न रह जाए, जहां आधुनिक टेक्नोलॉजी का लाभ समाज के आखिरी छोर तक पहुंचे, तथा
- एक ऐसा नया भारत, जो चौथी औद्योगिक क्रांति में अग्रणी भूमिका निभाए और विश्व मंच में नई ऊंचाइयों पर पहुंचे।

माननीय सदस्यगण, ऐसे नए भारत के लिए तथा लोगों की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए, मेरी सरकार हर क्षेत्र में परिवर्तन लाने के लिए सराहनीय गति और निर्णय क्षमता दिखाते हुए काम कर रही है। सरकार द्वारा पिछले पाँच वर्षों में जमीनी स्तर पर किए गए सुधारों का ही परिणाम है कि अनेक क्षेत्रों में भारत की अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में अभूतपूर्व सुधार आया है।

वर्ल्ड बैंक की Ease of Doing Business की रैंकिंग में भारत 79 स्थान ऊपर चढ़ते हुए आज 63वें स्थान पर है। Resolving Insolvency की रैंकिंग में भारत 108वें स्थान से 52वें स्थान पर और Global Innovation रैंकिंग में देश 74वें से 52वें स्थान पर पहुंच गया है। Logistics Performance Index में भारत ने अपनी अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में 10 अंकों का सुधार किया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की Travel and Tourism Competitiveness रैंकिंग में भारत 52वें स्थान से 34वें स्थान पर पहुंच गया है।

अलग-अलग क्षेत्रों में ये सुधार अंतरराष्ट्रीय जगत को भी एक आह्वान है कि भारत ने पिछले 5-6 वर्षों में किस तरह अपनी बुनियाद मजबूत की है और भारत के लोग कैसे नए भारत के निर्माण के लिए उत्साहित हैं।

माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार, **‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’** के मंत्र पर चलते हुए, पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम कर रही है। 8 करोड़ गरीबों को मुफ्त गैस कनेक्शन, 2 करोड़ गरीबों को घर, लगभग 38 करोड़ गरीबों के बैंक खाते, 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा, 24 करोड़ लोगों को बीमा सुरक्षा कवच, 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त बिजली कनेक्शन पूरी पारदर्शिता के साथ और बिना भेदभाव के दिया गया है। मेरी सरकार की योजनाओं ने हर धर्म, हर क्षेत्र के गरीबों के हित में, समानता के साथ, सहायता व सुविधाएं पहुंचाई हैं और इसलिए देश के लोगों का विश्वास भी अर्जित किया है।

माननीय सदस्यगण, बंगाल की धरती के महान सपूत और जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व वाली सरकार में उद्योग मंत्री रहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, लोकसभा में कहा था कि- **"एक लोकतांत्रिक संघीय राज्य में, एक इकाई के नागरिकों के मौलिक अधिकार किसी अन्य इकाई के नागरिकों से अलग नहीं हो सकते। क्या जम्मू-कश्मीर के लोग उन मूलभूत अधिकारों के हकदार नहीं हैं, जो हमने शेष भारत के लोगों को दिए हैं?"**

आज सात दशक बाद पूरे देश में इस बात की खुशी है कि डॉक्टर मुखर्जी समेत करोड़ों स्वतंत्रता सेनानियों का सपना साकार हुआ है और जम्मू-कश्मीर

एवं लद्दाख के लोगों को, वहां के दलितों और महिलाओं को भी वही अधिकार मिले हैं, जो बाकी देशवासियों को प्राप्त हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा दो तिहाई बहुमत से संविधान के अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 ए को हटाया जाना, न सिर्फ ऐतिहासिक है बल्कि इससे जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के समान विकास का भी मार्ग प्रशस्त हुआ है। मैं इस सदन के माध्यम से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों को विकास की मुख्यधारा से जुड़ने के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

माननीय सदस्यगण, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का तेज विकास, वहां की संस्कृति और परंपराओं की रक्षा, पारदर्शी व ईमानदार प्रशासन और लोकतंत्र का सशक्तीकरण, मेरी सरकार की प्राथमिकताओं में हैं। राष्ट्रपति शासन के दौरान और केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विकास की सभी परियोजनाओं में तेजी आई है।

वर्ष 2018 के अंत में जम्मू-कश्मीर की 4,400 से अधिक पंचायतों में शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हुए थे। स्वतंत्रता के बाद पहली बार वहां 300 से अधिक Block Development Councils के चुनाव भी कराए गए हैं। अब वहां के लोगों को स्वच्छ भारत अभियान, उज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, उजाला योजना, DBT तथा खाद्य सब्सिडी का पारदर्शी तरीके से पूरा लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जहां मार्च 2018 तक जम्मू-कश्मीर में लगभग 3,500 घर बनाए गए थे, वहीं दो साल से भी कम समय में 24,000 से ज्यादा घरों का निर्माण पूरा किया गया है।

इसके अलावा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में कनेक्टिविटी, सिंचाई, अस्पताल, पर्यटन से जुड़ी योजनाओं एवं IIT, IIM, AIIMS जैसे उच्च शिक्षा के संस्थानों की स्थापना का काम भी तेजी से चल रहा है। जम्मू-कश्मीर में सेब की सीधी खरीद के लिए NAFED को जिम्मेदारी दी गई है। इससे कश्मीर घाटी के सेब उत्पादकों को विशेषतौर पर लाभ मिला है।

माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की सफलता ने तथा सरकार द्वारा लिए गए ऐतिहासिक फैसलों ने, देशवासियों की

अपेक्षाएं भी बढ़ाई हैं और सरकार का दायित्व भी।

देशवासियों की बरसों से यह अपेक्षा थी कि वे सुगमता के साथ करतारपुर साहिब के दर्शन कर पाएं। मेरी सरकार ने रिकॉर्ड समय में करतारपुर साहिब कॉरिडोर का निर्माण करके, गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के अवसर पर इसे राष्ट्र को समर्पित किया। गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व को देश और दुनिया में पूरे मान-सम्मान के साथ मनाने का अवसर मिलना, मेरी सरकार के लिए सौभाग्य की बात है। मेरी सरकार द्वारा श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व भी पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाएगा।

माननीय सदस्यगण, देश की राजधानी दिल्ली में रहने वाले 40 लाख से ज्यादा लोग, बरसों से इस अपेक्षा में जी रहे थे कि एक दिन उन्हें अपने घर का मालिकाना हक और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार मिलेगा। दिल्ली की 1,700 से अधिक कॉलोनियों में रहने वाले लोगों की इस अपेक्षा को भी सरकार ने पूरा किया है।

देश के किसानों, खेतिहर मजदूरों, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों तथा छोटे व्यापारियों की अपेक्षा थी कि वृद्धावस्था में उनकी सहायता के लिए पेंशन योजना शुरू हो। मेरी सरकार ने न सिर्फ उनकी इच्छा को पूरा किया बल्कि अब तक इन पेंशन योजनाओं से करीब 60 लाख लाभार्थी जुड़ चुके हैं।

पूज्य बापू ने स्वच्छता को ईश्वर की उपासना से बढ़कर बताया था। पिछले 2 अक्टूबर को गांधी जी की 150वीं जयंती पर, देश के ग्रामीण इलाकों ने, खुद को खुले में शौच से मुक्त घोषित करके, राष्ट्रपिता के प्रति सच्ची श्रद्धा व्यक्त की है। अब हम सभी का दायित्व है कि इस दशक में अपने शहरों और गांवों को और अधिक स्वच्छ और सुंदर बनाएं।

माननीय सदस्यगण, आज भी देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 15 करोड़ घर ऐसे हैं, जहां पाइप से पानी की सप्लाई नहीं होती है। घर में पानी के न होने से हमारी बहनों-बेटियों का जीवन सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाता है। साथ ही, दूषित पानी से पूरे परिवार का स्वास्थ्य खराब होता है। देश के गांवों में, हर

घर तक पर्याप्त मात्रा में शुद्ध पेय जल पहुंचे, इसके लिए मेरी सरकार ने जल जीवन मिशन शुरू किया है। केंद्र सरकार, सभी राज्य सरकारें, स्थानीय निकाय और स्वयंसेवी संस्थाएं मिलकर इस अभियान को जन-आंदोलन में बदल रही हैं। इस योजना पर आने वाले समय में 3 लाख 60 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मेरी सरकार ने, देश के सबसे संकटग्रस्त ऐसे सात राज्यों में जहां भूजल का स्तर तेजी से घट रहा है वहां विशेष तौर पर अटल भूजल योजना शुरू की है।

माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार का सबका साथ - सबका विकास - सबका विश्वास का मंत्र देश के प्रत्येक नागरिक के साथ ही देश के अलग-अलग भूभाग और राज्यों से भी जुड़ा हुआ है। मेरी सरकार मानती है कि जैसे समाज के आखिरी छोर पर खड़े व्यक्ति के विकास को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, वैसे ही विकास में पीछे रह गए क्षेत्रों के विकास को भी प्राथमिकता दी जाए।

देश के 112 जिलों को Aspirational District - आकांक्षी जिले का दर्जा देकर इनमें गरीबों के विकास से जुड़ी एक-एक योजना पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है। राज्य सरकारों द्वारा भी इन जिलों में युवा और अनुभवी अफसरों का तालमेल बिठाकर सही नियुक्तियां की गईं। इसका परिणाम है कि इन जिलों में विकास के अनेक मापदंडों में प्रभावी सुधार हुआ है और कई जिले अब अपने राज्य के औसत के बराबर आ चुके हैं। मैं प्रत्येक आकांक्षी जिले की टीम को इस सदन के माध्यम से बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं।

माननीय सदस्यगण, दिल्ली से नॉर्थ ईस्ट की भौगोलिक दूरी से अधिक, वहां के लोगों को, दिलों की दूरियां खटकती थीं। मेरी सरकार ने पिछले पाँच वर्षों में अथक परिश्रम करके इस स्थिति को बदला है। नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी बढ़ाने, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने और लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए अभूतपूर्व गति से कार्य किया जा रहा है। सरकार के प्रयासों की वजह से वर्ष 2022 तक सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड की राजधानियां रेल नेटवर्क से जुड़ जाएंगी। अगरतला-अखौरा रेल लिंक पर भी काम तेजी से चल रहा है। वर्ष 2022 में ही अरुणाचल प्रदेश के 'हलोंगी' में बन रहे नए एयरपोर्ट का काम भी पूरा हो जाएगा।

इसके अलावा गुवाहाटी में एम्स, नुमालीगढ़ में बायो-रिफाइनरी, मणिपुर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का भी निर्माण तेज गति से हो रहा है। हाल ही में सरकार द्वारा नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड प्रोजेक्ट के लिए लगभग 9 हजार करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। यह प्रोजेक्ट नॉर्थ ईस्ट के सभी 8 राज्यों में Gas Based Economy का आधार बनेगा।

पाँच दशकों से चली आ रही बोडो समस्या को समाप्त करने के लिए केंद्र और असम सरकार ने हाल ही में बोडो संगठनों के साथ ऐतिहासिक समझौता किया है। इस समझौते से, ऐसी जटिल समस्या, जिसमें 4 हजार से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई, उसका समाधान निकला है। समझौते के बाद बोडो समुदाय के विकास के लिए सरकार द्वारा 1,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। त्रिपुरा, मिजोरम, केंद्र सरकार और ब्रू जनजाति के बीच हुए ऐसे ही एक और ऐतिहासिक समझौते से, न सिर्फ दशकों पुरानी समस्या हल हुई है बल्कि इससे ब्रू जनजाति के हजारों लोगों के लिए सुरक्षित जीवन भी सुनिश्चित हुआ है।

माननीय सदस्यगण, देश के आदिवासी भाई-बहनों को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए मेरी सरकार संकल्पबद्ध है। पहली बार किसी सरकार द्वारा वन उत्पादों पर MSP का लाभ दिया गया है। मेरी सरकार का विशेष बल आदिवासियों के स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास पर है। सरकार द्वारा कुछ सप्ताह पहले ही, देश में 400 से ज्यादा एकलव्य मॉडल रेज़िडेंशियल स्कूल खोलने का अभियान शुरू किया गया है। हाल ही में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को लोकसभा और विधानसभा में मिलने वाला आरक्षण भी, अगले दस वर्षों के लिए बढ़ाया जा चुका है।

माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार अल्पसंख्यक वर्ग की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक प्रगति के लिए भी निरंतर प्रयासरत है। हुनर हाट के जरिए अल्पसंख्यक वर्ग के 2 लाख 65 हजार हुनरमंद कारीगरों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। मुस्लिम छात्र-छात्राओं की शिक्षा निर्बाध जारी रहे, इसके लिए बड़ी तादाद में स्कॉलरशिप दी गयी है।

मेरी सरकार के विशेष आग्रह पर सउदी अरब ने हज कोटा में अभूतपूर्व वृद्धि की थी जिस वजह से इस बार रिकार्ड 2 लाख भारतीय मुस्लिमों ने हज में इबादत की। भारत पहला ऐसा देश है जिसमें हज की पूरी प्रक्रिया डिजिटल और ऑनलाइन की जा चुकी है। सरकार देशभर में वक्फ संपत्तियों का शत प्रतिशत डिजिटाइजेशन भी करा रही है जिससे इन संपत्तियों का उपयोग मुस्लिम समुदाय के भले के लिए किया जा सके।

माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार द्वारा दिव्यांगजनों की आशाओं-अपेक्षाओं के प्रति पूरी संवेदनशीलता के साथ काम किया जा रहा है। आरक्षण में वृद्धि, कानूनी अधिकार में वृद्धि के साथ ही सरकार ने एक हजार से ज्यादा सरकारी भवनों और 700 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों को सुगम्य बनाया है। बीते 5 वर्षों में हजारों कैंप लगाकर दिव्यांगजनों को लगभग 900 करोड़ रुपए के उपकरण उपलब्ध कराये गए। सरकार द्वारा दिव्यांगजनों का नेशनल डेटाबेस भी बनाया जा रहा है और 25 लाख से ज्यादा दिव्यांगजनों को e-Unique Identification Card जारी किए जा चुके हैं। मेरी सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में एक विशेष प्रयास शुरू किया था Indian Sign Language Dictionary का। मुझे सदन को यह जानकारी देते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 6 हजार शब्दों की एक विशेष डिक्शनरी बनाई जा चुकी है।

माननीय सदस्यगण, भारत ने हमेशा सर्वपंथ समभाव पर विश्वास किया है। लेकिन विभाजन के समय सबसे ज्यादा प्रहार भारत और भारतवासियों के इसी विश्वास पर किया गया। विभाजन के बाद बने माहौल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि- **"पाकिस्तान के हिंदू और सिख, जो वहां नहीं रहना चाहते, वे भारत आ सकते हैं। उन्हें सामान्य जीवन मुहैया कराना भारत सरकार का कर्तव्य है।"** पूज्य बापू के इस विचार का समर्थन करते हुए, समय-समय पर अनेक राष्ट्रीय नेताओं और राजनीतिक दलों ने भी इसे आगे बढ़ाया। हमारे राष्ट्र निर्माताओं की उस इच्छा का सम्मान करना, हमारा दायित्व है। मुझे प्रसन्नता है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा नागरिकता संशोधन कानून बनाकर, उनकी इच्छा को पूरा किया गया है। विशेषकर ऐसे समय में जब देश गांधी जी की 150वीं

जयंती का पर्व मना रहा हो, तब आप सभी सांसदों ने उनकी भावना को सर्वोपरि रखा है। मैं संसद के दोनों सदनों का तथा सभी सांसदों का अभिनंदन करता हूँ।

माननीय सदस्यगण, हम सभी इस बात के साक्षी रहे हैं कि समय के साथ पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर होने वाला अत्याचार और बढ़ा है। हाल ही में ननकाना साहिब में जो हुआ, उसे हम सभी ने देखा है। हम सभी का यह भी दायित्व है कि पाकिस्तान में हो रहे अत्याचार से पूरा विश्व परिचित हो।

मैं पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार की निंदा करते हुए, विश्व समुदाय से इसका संज्ञान लेने और इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने का भी आग्रह करता हूँ।

माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार यह पुनः स्पष्ट करती है कि भारत में आस्था रखने वाले और भारत की नागरिकता लेने के इच्छुक दुनिया के सभी पंथों के व्यक्तियों के लिए जो प्रक्रियाएं पहले थीं, वे आज भी वैसी ही हैं। किसी भी पंथ का व्यक्ति इन प्रक्रियाओं को पूरा करके, भारत का नागरिक बन सकता है। शरणार्थियों को नागरिकता देने से किसी क्षेत्र और विशेषकर नॉर्थ ईस्ट पर कोई सांस्कृतिक प्रभाव न पड़े, इसके लिए भी सरकार ने कई प्रावधान किए हैं।

माननीय सदस्यगण, भारतभूमि के महान संत कवि, थिरुवल्लुवर ने कहा था

‘उरुवार उलगत्तार्क आणिअः ताट्राद, एरुवारै एल्लाम् पोरुत्त’

अर्थात्, "किसान, धुरी की कील के समान है जो पूरे विश्व को संभालकर रखता है। वह उन सबके भार का वहन करता है जो खेती नहीं कर सकते।"

हमारा देश हमारे अन्नदाता किसानों का ऋणी है जिनके परिश्रम से हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हैं। निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करने वाले किसानों की जिंदगी बदले, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो, ये मेरी सरकार की प्राथमिकता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए आने वाले वर्षों में सरकार 25 लाख करोड़ रुपए की राशि खर्च करने जा रही है। किसानों की आय को दोगुना

करने के लिए सरकार द्वारा आय केंद्रित व्यवस्था विकसित करने की रणनीति पर काम किया जा रहा है।

माननीय सदस्यगण, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 8 करोड़ से ज्यादा किसान-परिवारों के बैंक खाते में 43 हजार करोड़ रुपए से अधिक राशि जमा कराई जा चुकी है। इसी महीने 2 जनवरी को, एक साथ 6 करोड़ किसानों के बैंक खाते में 12 हजार करोड़ रुपए ट्रांसफर करके मेरी सरकार ने रिकॉर्ड बनाया है।

मेरी सरकार किसानों को लागत का डेढ़ गुना मूल्य देने के लिए समर्पित भाव से काम कर रही है। खरीफ और रबी की फसलों के लिए MSP में लगातार की गई वृद्धि इसी दिशा में उठाया गया कदम है। सरकार के प्रयासों से दलहन और तिलहन की खरीद में 20 गुना से अधिक की बढ़ोतरी हुई है।

माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार खेती के वैकल्पिक उपायों पर भी जोर दे रही है। क्लस्टर आधारित बागवानी के साथ ही ऑर्गेनिक खेती के प्रचार और प्रसार पर भी काम हो रहा है। शहद उत्पादन को लेकर किए गए सरकार के प्रयासों से शहद उत्पादन में लगभग 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। शहद का निर्यात भी दोगुने से अधिक हो गया है। इसी उपलब्धि को और बढ़ाने के लिए नेशनल बी-कीपिंग एंड हनी मिशन को स्वीकृति दी गई है।

नए मत्स्यपालन विभाग के माध्यम से मछुआरों की आय और मछली का उत्पादन, दोनों को दोगुना करने का लक्ष्य है। देश के 50 करोड़ से अधिक पशुधन को स्वस्थ रखने का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। नेशनल एनीमल डिज़ीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत पशुओं के Foot and Mouth Disease से बचाव के लिए उनके टीकाकरण व अन्य उपायों पर 13 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं।

माननीय सदस्यगण, प्राकृतिक आपदा से किसान को राहत दिलाने के लिए मेरी सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर संवेदनशीलता से काम कर रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत औसतन प्रतिवर्ष साढ़े 5 करोड़ से ज्यादा

किसान बहुत कम प्रीमियम पर अपनी फसलों का बीमा करा रहे हैं। इस योजना के तहत बीते तीन वर्षों में किसानों को लगभग 57 हजार करोड़ रुपए की क्लेम राशि का भुगतान किया गया है।

किसानों के लिए शुरू किए गए ऑनलाइन राष्ट्रीय बाज़ार यानि e-NAM का प्रभाव भी अब दिखाई देने लगा है। देश के 1 करोड़ 65 लाख किसान एवं करीब सवा लाख व्यापारी इससे जुड़ चुके हैं। लगभग 90 हजार करोड़ रुपए का कारोबार इस प्लेटफॉर्म पर हो चुका है। इस दशक में e-NAM को और प्रभावी बनाने के लिए 400 से ज्यादा नई मंडियों को इससे जोड़ने पर काम चल रहा है।

माननीय सदस्यगण, व्यक्ति के स्वास्थ्य का प्रभाव परिवार और देश, दोनों के विकास पर पड़ता है। मेरी सरकार स्वास्थ्य को लेकर समग्रता के साथ काम कर रही है। प्रिवेंटिव हेल्थकेयर और क्यूरेटिव हेल्थकेयर, हर स्तर पर गंभीर प्रयास हो रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान, जल जीवन मिशन, पोषण अभियान, फिट इंडिया अभियान, आयुष्मान भारत योजना, ऐसी अनेक योजनाएं देशवासियों के स्वास्थ्य में सुधार लाने में सहायक हो रही हैं।

आयुष्मान भारत योजना का व्यापक असर देश के हेल्थ सेक्टर पर देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अब तक 75 लाख गरीब अपना मुफ्त इलाज करा चुके हैं। इसके साथ ही 27 हजार से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी तैयार हो चुके हैं।

माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार द्वारा लिए गए फैसलों की वजह से, गरीब और मध्यम वर्ग का इलाज का खर्च काफी कम हुआ है। एक हजार से अधिक जरूरी दवाइयों की कीमत नियंत्रित होने से मरीजों के 12,500 करोड़ रुपये बचे हैं। स्टेंट्स और नी-इम्प्लांट्स की कीमत कम होने से लाखों मरीजों को नया जीवन मिला है। अब प्रतिदिन 5 से 7 लाख मरीज गंभीर बीमारियों की दवाई 6,000 से अधिक जन औषधि केंद्रों से कम कीमत में खरीद रहे हैं।

मेरी सरकार ने नेशनल मेडिकल कमीशन बनाकर मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में सुधार की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। इसी वर्ष देश में 75 नए

मेडिकल कॉलेज बनाने की स्वीकृति दी गई है, जिससे देश में मेडिकल की लगभग 16 हज़ार MBBS और 4 हज़ार से अधिक PG सीटों की बढ़ोतरी होगी। इसके अतिरिक्त देश के विभिन्न क्षेत्रों में 22 AIIMS की स्वीकृति दी जा चुकी है जिनका निर्माण प्रगति पर है।

मेरी सरकार, महिला स्वास्थ्य के लिए भी विशेष प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के तहत देश की 1 करोड़ 20 लाख महिलाओं को लगभग 5 हज़ार करोड़ रुपए सरकार द्वारा सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। मिशन इंद्रधनुष के तहत 3 करोड़ 50 लाख शिशुओं और लगभग 90 लाख गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण हो चुका है। दलितों और आदिवासी क्षेत्रों में इन योजनाओं का लाभ विशेष तौर पर देखने को मिल रहा है। मेरी सरकार ने सिर्फ एक रुपये में 'सुविधा' नामक ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन देने की भी शुरुआत की है।

माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार के प्रयासों से, महिला उद्यमशीलता और आजीविका को बढ़ावा देने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप अभियान से अभी तक 6 करोड़ 60 लाख से अधिक महिलाएं जुड़ चुकी हैं। इन महिलाओं को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। कार्य में समान अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पहली बार अंडर ग्राउंड माइन्स में तथा ओपन कास्ट माइन्स में महिलाओं को रात्रि में भी काम करने की अनुमति दी गई है। समानता के इसी उद्देश्य के साथ पहली बार सैनिक स्कूलों में बेटियों के दाखिले को स्वीकृति दी गई है। मिलिट्री पुलिस में महिलाओं की नियुक्ति का काम भी जारी है। भारतीय वायुसेना ने पहली बार फाइटर स्ट्रीम और डिफेंस अटैची के रूप में भी उन्हें नया अवसर दिया है।

माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। महिला सुरक्षा की दृष्टि से देश में 6 सौ से अधिक वन स्टॉप सेंटर बनाए जा चुके हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों की पहचान करने के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार किया गया है। ऐसे मामलों में न्याय तेज़ी से मिले, इसके लिए देशभर में 1 हज़ार से ज्यादा फास्ट

ट्रैक स्पेशल कोर्ट बनाए जाएंगे। यह भी तय किया गया है कि Women Help Desk का विस्तार, देश के हर पुलिस स्टेशन में किया जाए। बच्चों के यौन शोषण जैसे जघन्य अपराधों में सरकार ने फांसी तक की सज़ा का प्रावधान किया है।

माननीय सदस्यगण, 21वीं सदी को ज्ञान की सदी कहा जाता है और सरकार की प्राथमिकता इस क्षेत्र में युवा लीडरशिप तैयार करने पर भी है। इस दशक में रिसर्च, इनोवेशन, इंक्यूबेशन और स्टार्टअप के क्षेत्र का नेतृत्व हमारे देश के युवा ही करेंगे। इस दिशा में मेरी सरकार द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों का लाभ युवा शक्ति को निरंतर मिल रहा है। आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट अप इकोसिस्टम भारत में है। स्टार्ट अप इंडिया अभियान के तहत देश में 27 हज़ार नए स्टार्ट अप्स को मान्यता दी जा चुकी है। पिछले पाँच वर्षों में देश में प्रदान किए गए पेटेंट की संख्या 4 गुना हो गई है और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन में 5 गुना वृद्धि दर्ज की गई है।

स्किल इंडिया अभियान, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के माध्यम से युवाओं में कौशल विकास के साथ ही उन्हें स्वरोज़गार के लिए जरूरी धन भी मुहैया कराया जा रहा है। मुद्रा योजना के तहत देश में 5 करोड़ 54 लाख से ज्यादा नए उद्यमियों ने ऋण लिया है। इस योजना के तहत अब तक 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का ऋण दिया जा चुका है।

माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार शिक्षा की गुणवत्ता और Innovation को बढ़ावा देने वाली योजनाओं पर बल दे रही है। Higher Education Funding Agency – HEFA के माध्यम से देश के 75 शिक्षा संस्थानों के आधुनिकीकरण के लिए 37 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। सरकार द्वारा केंद्रीय विद्यालयों में लगभग 7 हजार और उच्च शिक्षा में 12 हजार शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पहल की गई है। ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा 'स्वयं 2' की शुरुआत भी की गई है।

मुझे आप सबको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि देश के इतिहास में पहली बार उच्च शिक्षा में छात्राओं ने छात्रों के मुकाबले ज्यादा संख्या में दाखिला लिया है।

माननीय सदस्यगण, खेल के क्षेत्र में भारत को विश्व की महत्वपूर्ण शक्ति बनाने की पूरी संभावना हमारे युवाओं में है। खेलो इंडिया अभियान और ओलंपिक पोडियम स्कीम सहित अनेक योजनाओं के तहत, युवा टैलेंट की पहचान की जा रही है, उन्हें उच्च स्तर पर मुकाबले के लिए उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है। कुछ दिन पहले ही खेलो इंडिया अभियान का तीसरा चरण सफलतापूर्वक गुवाहाटी में संपन्न हुआ है। उल्लेखनीय है कि इस बार इसमें 80 नए नेशनल रिकॉर्ड्स बने हैं जिसमें से 56 महिला खिलाड़ियों ने बनाए हैं।

माननीय सदस्यगण, इस वर्ष एक अगस्त को महान स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक की सौवीं पुण्यतिथि है। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज को जन्मसिद्ध अधिकार बताने वाला कालजयी आह्वान किया था। स्वराज की सिद्धि के बाद देश ने सुराज प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना शुरू किया। सुराज के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ते हुए मेरी सरकार तीन स्तरों पर कार्य कर रही है:

- पहला- सरकार की कार्यसंस्कृति में परिवर्तन तथा संगठनों का सशक्तीकरण,
- दूसरा- पारदर्शिता के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल,
- और तीसरा- जमीनी स्तर पर स्वस्थ स्पर्धा और जनभागीदारी को बढ़ावा ।

माननीय सदस्यगण, "Minimum Government, Maximum Governance" के मूल सिद्धांत पर चलते हुए सरकार द्वारा अनेक Reform किए गए हैं। हाल ही में 58 और कानूनों को समाप्त करने के बाद अब सरकार द्वारा समाप्त किए गए कानूनों की संख्या लगभग 1500 तक पहुंच गई है। पारदर्शिता लाने के लिए हर स्तर की नियुक्ति प्रक्रिया में Reform किया जा रहा है। ग्रुप बी के अधिकांश और ग्रुप सी पदों में इंटरव्यू समाप्त किए जाने का लाभ युवाओं को हो रहा है।

माननीय सदस्यगण, योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए Silos का समाप्त होना और विभागों में समन्वय बहुत आवश्यक है। इस दिशा में पिछले वर्ष अक्टूबर में सिविल सेवा की 20 से अधिक सेवाओं के अफसरों के लिए

कॉमन फाउंडेशन कोर्स का आयोजन, एक महत्वपूर्ण कड़ी है। हाल ही में भारतीय रेल के प्रबंधन को भी पुनर्गठित किया गया है। देश के अलग-अलग ट्राइब्यूनल्स और प्रभावी तरीके से काम कर सकें, इसके लिए ट्राइब्यूनल सिस्टम को भी सुधारा जा रहा है। योजनाओं को लक्ष्योन्मुख बनाने के लिए सरकार द्वारा नए मंत्रालयों का गठन भी किया गया है। सरकार द्वारा कौशल विकास मंत्रालय एवं जलशक्ति मंत्रालय का गठन इसी सोच का उदाहरण है।

माननीय सदस्यगण, सरकारी सेवाओं और सरकारी लाभ की तेज और सटीक डिलिवरी मेरी सरकार की विशेषता रही है। ऐसा इसलिए संभव हुआ है क्योंकि टेक्नोलॉजी को अभूतपूर्व स्तर पर सुशासन का आधार बनाया गया है। पारदर्शिता के साथ लाभार्थियों की पहचान, लाभार्थियों के बैंक खाते में शत प्रतिशत राशि का ट्रांसफर और योजनाओं की मॉनीटरिंग में आधुनिक टेक्नोलॉजी के उपयोग ने गरीब और मध्यम वर्ग का जीवन आसान बनाया है। अब इस दशक में यही टेक्नोलॉजी, देशवासियों के जीवन की गुणवत्ता सुधारने में भी उनकी मदद करेगी।

माननीय सदस्यगण, हम सभी जानते हैं कि औद्योगिक क्रांति Industry 4.0 का आधार डिजिटल टेक्नोलॉजी है। मेरी सरकार द्वारा 21वीं सदी में औद्योगिक क्रांति का पूरा लाभ उठाने के लिए, डिजिटल इंडिया अभियान के माध्यम से Digital Access, Digital Inclusion और Digital Empowerment पर अभूतपूर्व बल दिया गया है। देश को इस बात पर गर्व है कि पिछले पाँच वर्षों में भारत में विकसित हुई डिजिटल व्यवस्थाएं, विश्व के अनेक देशों के लिए प्रेरणा बन रही हैं।

माननीय सदस्यगण, आज देश में 121 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास आधार कार्ड है तथा लगभग 60 करोड़ लोगों के पास Rupay कार्ड है। दिसंबर 2019 में UPI के माध्यम से रिकॉर्ड 2 लाख करोड़ रुपए का लेन-देन हुआ है। हाल ही में सरकार ने BHIM App का नया वर्जन भी लॉन्च किया है।

JAM यानि जनधन-आधार और मोबाइल की त्रिशक्ति का इस्तेमाल करते हुए सरकार द्वारा अपनी लगभग 450 योजनाओं को DBT-डायरेक्ट बेनिफिट

ट्रांसफर से जोड़ा जा चुका है। DBTके माध्यम से पिछले 5 वर्षों में 9 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की गई है। लीकेज रुकने की वजह से मेरी सरकार द्वारा एक लाख 70 हजार करोड़ से अधिक रुपए, गलत हाथों में जाने से बचाए गए हैं।

गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, यानि GeM ने सरकारी खरीद में पारदर्शिता स्थापित की है। GeM से छोटे और लघु उद्यमियों को जहां सरकार के रूप में बहुत बड़ा बाजार मिला है वहीं इससे सरकार की पहुंच सीधे उद्यमी तक हुई है। पिछले तीन साल में सरकार के अलग-अलग विभागों द्वारा GeM के माध्यम से लगभग 40 हजार करोड़ रुपये का सामान खरीदा गया है।

टेक्नोलॉजी की मदद से मेरी सरकार ने इंस्पेक्टर राज को समाप्त करने में अनेक बड़े कदम उठाए हैं। अब हम इनकम टैक्स विभाग में भी ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं जहां मानव दखल यानि ह्यूमन इंटरफेस न हो। इस व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी और टैक्स विभाग की कार्यसंस्कृति में बड़ा सुधार आएगा।

माननीय सदस्यगण, शहरों और गांवों के बीच दूरी कम करने में भी टेक्नोलॉजी की बड़ी भूमिका है। भारतनेट योजना के तहत अब तक सवा लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा जा चुका है। 2014 में देश के ग्रामीण इलाकों में 60 हजार कॉमन सर्विस सेंटर्स थे, आज इनकी संख्या बढ़कर 3 लाख 65 हजार से ज्यादा हो गई है। इससे 12 लाख से ज्यादा ग्रामीणों को रोजगार मिला है। इन सेंटरों के माध्यम से सरकार अपनी 45 से ज्यादा सेवाएं ग्रामीण इलाकों तक पहुंचा रही है।

माननीय सदस्यगण, एक भारत, श्रेष्ठ भारत की भावना को सशक्त करते हुए मेरी सरकार टेक्नोलॉजी के माध्यम से देशवासियों के लिए एकीकृत व संगठित व्यवस्था विकसित कर रही है।

देश में Seamless Mobility सुनिश्चित करने के लिए कुछ दिन पहले One Nation, One FasTag लॉन्च किया गया है। One Nation One Mobility Card के माध्यम से देश के अलग-अलग राज्यों में, यातायात के अलग-अलग

माध्यमों में एक ही कार्ड के इस्तेमाल की सुविधा भी विकसित हुई है। सरकार द्वारा One Nation, One Ration Card की शुरुआत भी की जा रही है। One Nation, One Tax यानि GST ने भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश में पारदर्शी व्यापार को बढ़ावा दिया है। जब GST नहीं था तो दो दर्जन से ज्यादा अलग-अलग टैक्स देने होते थे। अब टैक्स का जाल तो समाप्त हुआ ही है, टैक्स भी कम हुआ है।

माननीय सदस्यगण, भारत जैसे संघीय प्रणाली वाले देश में विकास की गति बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि राज्यों के बीच विकास की योजनाओं में स्पर्धा भी हो और राज्य अपनी योजनाओं के अनुभव का लाभ दूसरे राज्यों को भी दें। मेरी सरकार इसलिए Competitive Cooperative Federalism - प्रतिस्पर्धी सहकारी संघवाद पर निरंतर बल देती रही है। सरकार द्वारा राज्यों को, जिला और गांव के स्तर पर Real Time Data से मिलने वाली रैकिंग प्रदान की जा रही है। इसका प्रभाव स्वच्छ भारत अभियान से लेकर, Ease of Doing Business तक और स्मार्ट सिटी मिशन से लेकर Aspirational District Programme तक में नजर आता है।

सरकारें सही योजनाएं बना सकें और लक्ष्य केंद्रित कार्य कर सकें इसके लिए Census से मिली जानकारी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। Census में इस बार यह प्रक्रिया तेजी से पूरी हो, इसलिए जानकारी एकत्रित करने के लिए डिजिटल तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है।

डिजिटल टेक्नोलॉजी के बढ़ते प्रसार के बीच मेरी सरकार निजता के संरक्षण के प्रति संकल्पित है। इस संकल्प की पूर्ति के लिए सरकार संसद में Data Protection Bill लेकर आई है।

माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए सभी स्टेकहोल्डर्स से बातचीत करके अर्थव्यवस्था में हर स्तर पर काम किया जा रहा है। दुनिया भर से आने वाली चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था की नींव मजबूत है। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 450 बिलियन डॉलर से भी ऊपर के ऐतिहासिक स्तर

पर है। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानि FDI भी निरंतर बढ़ रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार अप्रैल से अक्टूबर के बीच FDI 3 अरब डॉलर बढ़ा है।

वहीं, पब्लिक सेक्टर के छोटे बैंकों के विलय से बैंक सुदृढ़ हुए हैं और ऋण देने की उनकी क्षमता भी बढ़ी है। इस वित्त वर्ष की पहली छमाही में 12 सरकारी बैंक मुनाफे में रहे हैं। Insolvency and Bankruptcy Code की वजह से बैंकों और अन्य संस्थानों के करीब साढ़े तीन लाख करोड़ रुपए वापस भी आए हैं। कॉरपोरेट टैक्स में की गई कटौती और लेबर कोड से जुड़े कानून के बनने से भारत में कारोबार और आसान होगा।

माननीय सदस्यगण, अर्थव्यवस्था की गति एवं मैनुफेक्चरिंग और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए मेरी सरकार मेक इन इंडिया को सशक्त कर रही है। सरकार द्वारा तमिलनाडु और यूपी में दो डिफेंस कॉरिडोर और देश में 5 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी विकसित किए जा रहे हैं।

माननीय सदस्यगण, इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफेक्चरिंग में भारत विशेष रूप से तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। मोबाइल फोन, टीवी और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों की मैनुफेक्चरिंग को और गति देने के लिए नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स बनाई गई है। वर्ष 2014-15 में देश में जहां करीब 1 लाख 90 हजार करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का निर्माण हुआ, वहीं वर्ष 2018-19 में यह बढ़कर 4 लाख 58 हजार करोड़ रुपए तक पहुंच गया। 2014 में भारत में मोबाइल बनाने वाली सिर्फ 2 कंपनियां थीं। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश है। सरकार द्वारा ऑटोमोबाइल और रेलवे में भी मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित किया जा रहा है। वंदे भारत और तेजस एक्सप्रेस के रूप में पूरी तरह से भारत में बन रही आधुनिक रेलगाड़ियों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

माननीय सदस्यगण, आजादी के मूलमंत्र में एक भावना थी- आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत तब बनता है जब हर भारतीय, भारत में बनी हर वस्तु पर गर्व करे। मेरी सरकार **‘उज्वल कल के लिए लोकल’** के मंत्र पर विश्वास करती है। मैं पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक, देश के प्रत्येक जनप्रतिनिधि से, देश की हर सरकार से आग्रह करता हूं कि **‘उज्वल कल के लिए लोकल’**

को एक आंदोलन में परिवर्तित करें। मैं प्रत्येक भारतीय से भी आग्रह करूंगा कि वे स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता दें। स्थानीय स्तर पर बनी वस्तुओं का उपयोग करने पर आप अपने क्षेत्र के लघु उद्यमियों की बहुत बड़ी मदद करेंगे।

माननीय सदस्यगण, देश में 21वीं सदी का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये गरीब से लेकर मध्यम वर्ग की आशा-आकांक्षा रहती है। लोगों की इस अपेक्षा को पूरा करने के लिए अगले पाँच वर्ष में 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश किए जाएंगे। कनेक्टिविटी पर विशेष बल देते हुए, नए हाईवेज, नए वाटरवेज, नए एयरवेज, नए आईवेज के निर्माण पर भी सरकार ध्यान दे रही है।

देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रामीण सड़कों का बहुत बड़ा योगदान है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के जरिए देश के कोने-कोने तक ग्रामीण सड़कों का विस्तार हुआ है। इन सड़कों को सुदृढ़ बनाने और उन्हें स्कूल, अस्पताल व मंडियों से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का तीसरा चरण शुरू किया गया है। इसके तहत 1 लाख 25 हजार किलोमीटर की सड़कों का निर्माण और सुधार किया जाएगा।

सरकार द्वारा नदी जल मार्गों का विकास भी किया जा रहा है। दिसंबर 2019 में पहली बार नेशनल वाटर वे -2 के जरिए असम के पांडू तक कार्गो कंटेनर पहुंचा है। इस वर्ष जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट के जरिए गंगा नदी पर हल्दिया में मल्टी-मोडल टर्मिनल और फरक्का पर नैविगेशन लॉक पूरा कर लिया जाएगा। हमारा प्रयास है कि अगले वर्ष तक गंगा नदी पर बड़े ट्रांसपोर्ट कार्गो भी चलाये जा सकें।

शहरों में बेहतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लक्ष्य की तरफ तेज़ी से काम चल रहा है। मेट्रो सुविधा का विस्तार देश के 18 शहरों में हो चुका है। अभी तक 670 किलोमीटर मेट्रो लाइन चालू हो चुकी हैं और 930 किलोमीटर मेट्रो लाइनों पर काम चल रहा है। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे तथा ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे के निर्माण से दिल्ली और NCR के निवासियों को बहुत सुविधा हुई है।

माननीय सदस्यगण, .5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने में देश के टीयर 2 और टीयर 3 शहर, एक नई भूमिका के साथ उभर रहे हैं। स्वच्छता हो, सुविधाएं हों, स्टार्ट अप हों या फिर दूसरा कारोबार, छोटे शहरों की प्रगति उत्साहवर्धक है। साल 2014 के बाद से ही छोटे शहरों में स्टार्ट-अप्स की 45 से 50 प्रतिशत की वृद्धि दर देखी गई है। इसी तरह उड़ान योजना के तहत करीब 35 लाख लोग अब तक हवाई यात्रा कर चुके हैं। पिछले वर्ष 335 नए हवाई मार्गों की अनुमति दी गयी है। अनुमान है कि आने वाले वर्षों में, देश का आधे से ज्यादा डिजिटल लेन-देन इन्हीं टीयर-2 और टीयर-3 शहरों में होगा।

छोटे शहरों और नए मध्यम वर्ग के विकास को देखते हुए मेरी सरकार द्वारा उनकी अपेक्षाओं का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। पांच लाख रुपए तक की आय को करमुक्त करने से भी सबसे अधिक लाभ छोटे शहरों के मध्यम वर्ग को हुआ है। मध्यम वर्ग के जिन परिवारों की आय 18 लाख रुपए तक की है, उन्हें 20 वर्ष तक के होमलोन पर 5 से 6 लाख रुपए तक की बचत हो रही है। घरों को बनाने की अधूरी और लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा 25 हजार करोड़ रुपए के फंड की जो व्यवस्था की गई है, उसका लाभ भी सबसे ज्यादा मध्यम वर्ग को ही मिलेगा।

माननीय सदस्यगण, Clean energy के क्षेत्र में भारत विश्व में प्रभावी भूमिका निभा रहा है। सरकार के प्रयासों से अब देश में एलपीजी कवरेज 55 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 97 प्रतिशत हो गया है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का अब देश के 407 जिलों में विस्तार किया जा रहा है। अब हम Gas Based अर्थव्यवस्था की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं।

मेरी सरकार ने पर्यावरण की दृष्टि से अक्षय ऊर्जा के उत्पादन के लक्ष्य को बढ़ाकर 450 गीगावाट कर दिया है। प्रधानमंत्री-कुसुम योजना के माध्यम से देश में किसानों को 17 लाख से ज्यादा सोलर पंप देने का लक्ष्य रखा गया है। इसी तरह सरकार द्वारा सोलर रूफ टॉप कार्यक्रम के दूसरे चरण में 38 गीगावाट बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य है।

माननीय सदस्यगण, देशवासियों के प्रयास से भारत में पिछले चार साल में पेड़ और वन के क्षेत्र में 13 हजार वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। इसी तरह बाघों की संख्या जो 2014 में 2,226 थी वह जुलाई, 2019 में बढ़कर 2,967 हो चुकी है। देश में बाघों की बढ़ती संख्या संतोष का विषय है।

वायु और जल प्रदूषण से निपटने के लिए, देश के 102 शहरों में सरकार नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम भी लागू करने जा रही है। मुझे संतोष है कि सरकार द्वारा शुरू किए गए नमामि गंगे मिशन के सकारात्मक परिणाम भी दिखाई देने लगे हैं। इस मिशन के तहत 7 हजार करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स पर काम पूरा हो चुका है और 21 हजार करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स पर कार्य प्रगति पर है।

इन सारे प्रयासों का असर देश के पर्यटन क्षेत्र पर भी दिख रहा है। बीते कुछ वर्षों से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व काम किया गया है। हाल में देश की हैरिटेज बिल्डिंग्स के संरक्षण और सौंदर्यीकरण के लिए कोलकाता से एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना से तैयार हो रहे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से भी पर्यटन सेक्टर को मजबूती मिल रही है। दुनिया की सबसे ऊंची, सरदार पटेल की प्रतिमा 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' को देखने आने वाले पर्यटकों की संख्या भी नित नए रिकॉर्ड बना रही है।

माननीय सदस्यगण, देश की विरासत के संरक्षण और देश के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले महान व्यक्तित्वों के प्रति सम्मान व्यक्त करने को मेरी सरकार राष्ट्र निर्माण का प्रमुख अंग मानती है। इसी सोच के साथ सरकार द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में हमारी आदिवासी वीरांगनाओं एवं वीरों के सशक्त योगदान को समर्पित म्यूजियम्स का निर्माण, देश के अलग-अलग राज्यों में किया जा रहा है। सरकार द्वारा वर्ष 2022 में महान समाज सुधारक और देश को दिशा दिखाने वाले राजा राममोहन राय की 250वीं जयंती भी भव्यता के साथ मनाई जाएगी।

माननीय सदस्यगण, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का लक्ष्य, सदैव मानवता की सेवा रहा है। देश के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम के कारण

चंद्रयान-2 ने देश के युवाओं में टेक्नोलॉजी के प्रति नई ऊर्जा का संचार किया है। मेरी सरकार द्वारा चंद्रयान-3 को स्वीकृति दी जा चुकी है। ISRO द्वारा मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम- गगनयान तथा आदित्य-एक मिशन पर भी तेजी से कार्य हो रहा है।

माननीय सदस्यगण, बदलते समय में, देश की रक्षा से जुड़ी नई और जटिल चुनौतियों का सामना करने के लिए मेरी सरकार, सेनाओं को और भी सशक्त, प्रभावशाली और आधुनिक बना रही है। Chief of Defence Staff - CDS की नियुक्ति और Department of Military Affairs का गठन इसी दिशा में उठाया गया कदम है। इससे तीनों सेनाओं में समन्वय भी बढ़ेगा और सेनाओं के आधुनिकीकरण और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की प्रक्रिया भी तेज़ होगी।

भारत की सेनाओं और सुरक्षाबलों के पास पर्याप्त हथियार, सुरक्षा उपकरण तथा बुलेट प्रूफ जैकेट हों, इस पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में, अमेठी की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में रूस के साथ मिलकर दुनिया की आधुनिक रायफल AK203 का निर्माण शुरू किया जा रहा है। हाल ही में जब तेजस के Naval Prototype ने INS विक्रमादित्य पर लैंडिंग की और उड़ान भरी तो प्रत्येक भारतीय गर्व से भर उठा था। सरकार द्वारा अंतरिक्ष में भी सुरक्षा के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। A-Sat के सफल परीक्षण से भारत अंतरिक्ष में विशेष मारक क्षमता हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है।

माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार आतंकवाद के खतरे से देश को बाहर निकालने के लिए पूरे सामर्थ्य और दृढ़ता से काम कर रही है। आतंक के बदलते स्वरूप को देखते हुए नागरिकों की सतर्कता भी बहुत काम आती है। जनता के सहयोग से आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में कितनी मदद मिलती है ये जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में आई कमी से भी पता चलता है। मेरी सरकार ने आतंकवाद फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई के लिए सुरक्षा बलों को पूरी छूट दी हुई है। सरकार के निरंतर प्रयास से नॉर्थ ईस्ट में सुरक्षा की

स्थिति में भी बहुत सुधार हुआ है। देश में नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों का दायरा भी निरंतर सिमट रहा है।

माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार विदेश नीति को, देश की आर्थिक और सामरिक सुरक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण पहलू मानती है। हम अपने पड़ोसी देशों के साथ कनेक्टिविटी को बढ़ाकर आर्थिक विकास और संपन्नता को गति दे रहे हैं। "Neighbourhood First" की नीति हमारी प्राथमिकता है। अपने पड़ोसियों के साथ-साथ विश्व के अन्य देशों के साथ हमारे संबंध मजबूत हुए हैं। यही कारण है कि अनेक देशों ने अपना सर्वोच्च सम्मान भारत को दिया है। आसियान और अफ्रीकी देशों के साथ अपने सहयोग को हम नए स्तर पर ले जा रहे हैं।

भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बाद CDRI यानी Coalition on Disaster Resilient Infrastructure नाम की वैश्विक साझेदारी की पहल की है। आपदा से निपटने के लिए उठाए गए इस कदम से एक संवेदनशील विश्व शक्ति के रूप में भारत की भूमिका और सशक्त होने जा रही है।

माननीय सदस्यगण, जो दशक अभी शुरू हो रहा है, वह आने वाले समय में, वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति तय करेगा। इसी दशक में दुनिया को न्यू इंडिया का समावेशी, समृद्ध, समर्थ और सशक्त स्वरूप दिखाई देगा। इसलिए, इस सदन के प्रत्येक सदस्य का तथा हर देशवासी का यह कर्तव्य है कि वे अपनी पूरी क्षमता के साथ प्रयास करें और अपने-अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें।

देशहित के लिए देश का हर नागरिक अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक हो, कर्तव्य के प्रति समर्पित हो तथा यह कर्तव्य बोध हमारे नागरिक जीवन की प्राथमिकता बने, इस दिशा में हम सभी को काम करना चाहिए। आइए, हम सब 2020 के दशक को कर्तव्यों का दशक बनाएं।

हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी भी विचारधारा के नेता या समर्थक होने से पहले हम देश के नागरिक हैं। हमारे देश की प्रतिष्ठा हमारी दलीय प्रतिबद्धताओं से कहीं बढ़कर है।

मेरा यह विश्वास है कि आने वाले समय में भी हम सब मिलकर अपने देश के गौरवशाली अतीत से प्रेरणा लेते हुए, देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए, हर संभव प्रयास करेंगे और अपने प्रयासों में सफल भी होंगे ।

आइए, हम सब मिलकर नए भारत का सपना पूरा करें, हम सब मिलकर नया भारत बनाएं ।

जयहिंद !!!

Honourable Members, I am pleased to address the joint sitting of Parliament at the start of the third decade of 21st century. I once again extend my best wishes for the New Year and congratulate all Members of Parliament for being a witness to this historic occasion.

This decade is extremely important for India. In this decade, we will complete 75 years of our independence. In this decade, we all have to work together with new energy to give impetus to the making of a new India. With the efforts of my Government, a strong foundation has been laid in the last five years, to make this decade India's decade and this century India's century.

Whether it is Pujya Bapu's dream of Gram Swaraj, Babasaheb Ambedkar's principle of social justice, Nehru ji's dream of creating a modern India, Sardar Patel's resolve for Ek Bharat- Shreshtha Bharat, Deen Dayal Upadhyaya's goal of Antyodaya, Lohia ji's vision of social equality, we the people of India will together make these dreams a reality.

Honourable Members, The Constitution of India is the guiding light for all of us in fulfilling these dreams. Just a few weeks ago, on 26th November, 70 years of the Constitution have been completed. On that day, 12 crore citizens of the country, publicly read out the Preamble of the Constitution and renewed their commitment to the Constitution.

In addition, to protecting the rights of every citizen of our country, our Constitution makes the citizens of the country mindful of their duties. Further, our Constitution also places an expectation that the decisions taken through democratic processes will be accepted by the countrymen. At the same time, our Constitution expects the Parliament and every member present in this House to fulfil the hopes and aspirations of the countrymen and make the necessary laws, keeping the national interest paramount.

Honourable Members, I am happy that in the last 7 months, Parliament has set new standards in conducting its business. The performance during the first session of this Lok Sabha has set a new record in the last seven decades.

Due to my Government's strong commitment, the law against Triple Talaq ensuring justice to Muslim women and safeguarding their rights; the Consumer Protection Act providing new rights to the citizens; the Banning of Unregulated Deposit Schemes Act for protecting the savings of the poor; the Chit Funds Amendment Act protecting the poor from fraudulent chit fund schemes; the law enhancing punishment for sexual offences against children; Motor Vehicles Amendment Act aimed at reducing road accidents; and the law protecting the rights of the transgender persons - several such historic legislations have been enacted.

I congratulate every Member of Parliament for fulfilling this Constitutional responsibility.

Honourable Members, the faith reposed by the people of our country in our democratic institutions strengthens the foundation of our democracy. The maturity displayed by the countrymen after the Supreme Court's verdict on Ram Janmabhoomi is also laudable. My Government is of the firm view that mutual discussions and debates strengthen democracy. At the same time, any kind of violence in the name of protests weakens the society and the nation.

Honourable Members, in a democracy, nothing is more sacred than the mandate given by the people. The people of the country have given this mandate to my Government for the making of a new India.

- A new India which takes pride in the glory of our ancient culture and which enriches the 21st century world with the power of its knowledge.
- A new India, in which besides finding solutions to old problems, new chapters of development are written.
- A new India, in which adequate facilities and new opportunities for growth are available for the poor, dalits, women, youth, tribals and minorities.
- A new India, where every region develops, no region is left behind, where the benefits of modern technology reach the farthest end of society, and
- A new India, which is at the forefront of the fourth industrial revolution and which attains new heights at the global stage.

Honourable Members, for making such a new India and for fulfilling the expectations of the people, my Government is working

with commendable pace and decisiveness to bring about changes in every field. It is the outcome of reforms at the grassroots level ushered in by the Government in the last five years that there has been an unprecedented improvement in India's global ranking in several areas.

In the World Bank's **Ease of Doing Business** rankings, India has leapfrogged to the 63rd position, moving up by 79 places. In the **Resolving Insolvency** rankings, India has moved from 108th to 52nd position and in the **Global Innovation** rankings, from 74th to 52nd position. India has improved its international ranking by 10 points in the **Logistics Performance Index**. India has moved from 52nd to 34th position in the World Economic Forum's **Travel and Tourism Competitiveness** rankings.

These reforms in diverse areas are also a call to the international community to see how India has strengthened its foundations in the last 5-6 years and how keen the people of India are to build a new India.

Honourable Members, my Government is following the mantra of '**Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas**', and is working with full commitment and sincerity. Free gas connections to 8 crore poor, houses to 2 crore poor, bank accounts to about 38 crore poor, free treatment facility of up to Rs 5 lakh to 50 crore people, insurance cover to 24 crore people and free electricity connections to over 2.5 crore people have been provided; with complete transparency and without any discrimination. My Government has provided equitable access to benefits and facilities of its schemes for the poor people; of all religions and all regions, and has, thus, earned the trust of the people of the country.

Honourable Members, Dr. Shyama Prasad Mukherjee, the great son of Bengal and the Minister of Industry in the Government headed by Jawaharlal Nehru Ji, had said in the Lok Sabha: **“In a democratic federal state, the fundamental rights of the citizens of one constituent unit cannot vary vis-à-vis the citizens of another unit. Are not the people of Jammu and Kashmir entitled to the fundamental rights that we have given to the people of India minus Jammu and Kashmir?”**

Today, after seven decades, the whole country is happy that the dream of crores of freedom fighters including Dr. Mukherjee has come true and the people of Jammu-Kashmir and Ladakh, the dalits and women from that area have also got the same rights as the people in the rest of the country. The abrogation of Article 370 and Article 35A of the Constitution by two-thirds majority in both the Houses of Parliament is not only historic but has also paved the way for equitable development of Jammu - Kashmir and Ladakh. Through this House, I heartily congratulate the people of Jammu - Kashmir and Ladakh for joining the mainstream of development.

Honourable Members, rapid development of Jammu-Kashmir and Ladakh, preservation of their culture and traditions, transparent and honest administration and democratic empowerment are among the priorities of my Government. During the President’s Rule and since becoming a Union Territory, all the developmental projects in Jammu - Kashmir and Ladakh have gained momentum.

Towards the end of the year 2018, elections in more than 4,400 panchayats of Jammu -Kashmir were conducted in a peaceful manner. For the first time since independence, elections to more than 300 **Block Development Councils** have also been held there. The people there are

now getting full benefits under Swachh Bharat Abhiyan, Ujjwala Yojana, Ayushman Yojana, Ujala Yojana, **DBT** and food subsidy, in a transparent manner. Under the Pradhan Mantri Awas Yojana, while around **3,500** houses were built in Jammu - Kashmir till March 2018, in less than two years thereafter, construction of more than **24,000** houses has been completed.

Apart from this, works relating to connectivity, irrigation, hospitals, schemes related to tourism and establishment of institutes of higher education such as **IIT, IIM, AIIMS** are also proceeding at a rapid pace in Jammu -Kashmir and Ladakh. **NAFED** has been entrusted with the responsibility for the direct procurement of apples in Jammu - Kashmir. This has especially benefited the apple growers of Kashmir Valley.

Honourable Members, the success of the public welfare schemes of my Government and the historic decisions taken by the Government have increased the expectations of the countrymen, as well as the responsibilities of the Government.

For many years, the people of the country desired that they should be able to pay their respects at Kartarpur Sahib with ease. My Government has built the Kartarpur Sahib Corridor in record time, and dedicated it to the nation on the occasion of 550th birth anniversary of Guru Nanak Dev Ji. It is a privilege for my Government to have got the opportunity to celebrate the 550th birth anniversary of Guru Nanak Dev Ji with full veneration, within the country and abroad. The 400th birth anniversary of Shri Guru Tegh Bahadur Ji will also be celebrated in a befitting manner with full grandeur and devotion by my Government.

Honourable Members, over 40 lakh people living in the capital city of Delhi, had been living for many years in the hope that one day they would get the ownership rights of their homes and that they will be able to lead a dignified life. The Government has fulfilled this long awaited expectation of people living in more than 1,700 colonies of Delhi.

Farmers, agricultural labourers, unorganized sector labourers and small traders of the country had expectations of a pension scheme that would be of help to them in their old age. My Government has not only fulfilled their wish, but also has covered about 60 lakh beneficiaries so far, under these pension schemes.

Pujya Bapu always considered cleanliness next to Godliness. On the occasion of Gandhi ji's 150th birth anniversary, on 2 October last year, rural areas of the country have paid a befitting tribute to the Father of the Nation by declaring themselves free from open defecation. Now it is incumbent on all of us to make our cities and villages even more clean and beautiful in the coming decade.

Honourable Members, even today, there are about 15 crore houses without piped water supply in rural areas of the country. Our sisters and daughters face the maximum hardship due to lack of water supply in the house. Further, contaminated water adversely impacts the health of the entire family. In order to ensure the availability of sufficient quantity of potable drinking water to each rural household in the country, my Government has launched the Jal Jeevan Mission. Central Government, all State Governments, local bodies and voluntary organizations are working together to transform this Mission into a people's movement. In the coming days Rs 3 lakh 60 thousand crore will be spent on this scheme. My Government has launched the Atal Bhujal Yojana with

special focus on seven of the most vulnerable States of the country, where ground water level is depleting rapidly.

Honourable Members, my Government's mantra of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas is meant for every citizen and for every region and every State of the country. My Government believes that just as advancement of a person on the margins of society should be given high priority, the development of the areas left behind should also receive greater attention.

By according 112 districts the status of **Aspirational Districts**, the Government is paying special attention to each scheme relating to development of the poor living there. State Governments have also positioned the right mix of experienced and youthful officers in these districts. As a result, there has been impressive improvement in several development indicators in these districts and many districts have now come close to their State average. I congratulate and convey my best wishes to the team of each Aspirational District through this House.

Honourable Members, more than the physical distance of the North East from Delhi, it was the emotional disconnect that disheartened the people of the region. My Government has transformed this situation by working tirelessly during the last five years. Work is being done at an unprecedented pace in the North East to enhance connectivity, strengthen infrastructure and make people's lives easier. As a result of these efforts of the Government, by 2022, the capitals of Sikkim, Mizoram, Manipur and Nagaland will be connected to the rail network. The work on Agartala-Akhaura rail link is also progressing at a fast pace. In the year 2022, the construction of the new airport being built at 'Holongi' in Arunachal Pradesh will also be completed.

Besides this, construction of AIIMS in Guwahati, bio-refinery in Numaligarh and sports university in Manipur are also progressing at a fast pace. Recently, the Government has sanctioned about Rs 9,000 crore for the North East Gas Grid Project. This project will lay the foundation of a **Gas Based Economy** in all the 8 States of the North East.

The Central and Assam Governments have recently signed a historic agreement with the Bodo Organizations to bring an end to the 5 decade-old Bodo dispute. With this agreement, a complex problem, that has claimed more than 4000 lives, has been resolved. After this agreement, the Government will spend Rs1500 crore for the development of Bodo community. Similarly, another landmark agreement between Tripura, Mizoram, the Central Government and the Bru community has not only resolved a decades-old problem but has also ensured a secure life for thousands of people belonging to the Bru community.

Honourable Members, my Government is committed to bringing the brothers and sisters from the tribal community of the country into the mainstream of development. For the first time, Government has extended the benefit of **MSP** to forest produce. My Government's special emphasis is on the health, education and skill development of the tribals. Only a few weeks ago, the Government has launched a programme for opening more than 400 Eklavya Model Residential Schools in the country. Recently, reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Lok Sabha and State Assemblies has also been extended for the next ten years.

Honourable Members, my Government is also constantly striving for the social, economic and educational progress of the minority community. Through Hunar Haat, employment opportunities have been provided to 2 lakh 65 thousand skilled artisans belonging to the minority community. Scholarships have been granted in large numbers to Muslim students to enable them to continue their education without interruption.

On the special request of my Government, an unprecedented increase in Haj quota was made by Saudi Arabia as a result of which a record 2 lakh Indian Muslims performed the Haj this time. India is the first country where the entire process of Haj pilgrimage has been made digital and online. The Government is also undertaking 100 percent digitization of Waqf properties across the country so that these properties can be utilised for the welfare of the Muslim community.

Honourable Members, my Government is working with utmost sensitivity towards fulfilling the hopes and aspirations of the divyangjan. Along with increase in reservations and legal empowerment, more than 1000 Government buildings and more than 700 railway stations have been made accessible for divyangjan. In the last 5 years, aids and assistive devices worth Rs 900 crore were distributed to the divyangjan by organising camps. The Government is creating a national database of divyangjan and **e-Unique Identification Cards** have been issued to more than 25 lakh divyangjan. My Government, in its previous term, had undertaken a special initiative for preparing the **Indian Sign Language Dictionary**. It gives me pleasure to inform the House that a special dictionary of 6 thousand words has been prepared.

Honourable Members, India has always believed in the principle of equal respect for all faiths. However, at the time of Partition, this very belief of India and of its people came under the most severe attack. In

the environment prevailing in the aftermath of partition, the Father of the Nation Mahatma Gandhi had said: **“Hindus and Sikhs of Pakistan, who do not wish to live there, can come to India. It is the duty of the Government of India to ensure a normal life for them.”** Many national leaders and political parties have from time to time supported this idea of Pujya Bapu and further propagated it. It is our responsibility to honour this wish of the founding fathers of our nation. I am happy that both the Houses of Parliament have fulfilled this wish, by enacting the Citizenship Amendment Act. At a time when the country is celebrating the 150th birth anniversary of Gandhi ji, all of you have given paramount consideration to this sentiment. I congratulate both the Houses of Parliament and all the MPs for this.

Honourable Members, we have all been witness to the increase in the atrocities on minorities in Pakistan over time. We have all seen what happened in Nankana Sahib recently. It is the responsibility of all of us to bring the atrocities being committed in Pakistan to the notice of the global community.

While condemning the atrocities on the minorities in Pakistan, I urge the world community to take cognizance of it and take necessary steps in this regard.

Honourable Members, my Government would like to clarify once again that the procedures which have existed for people from all faiths of the world who believe in India and who wish to obtain Indian citizenship, remain unchanged. A person of any faith can follow these processes and become a citizen of India. The Government has made several provisions to ensure that granting citizenship to those who have

been compelled to take shelter in India does not have any adverse cultural impact on any region, especially the North East.

Honourable Members, the great saint poet of India, Thiruvalluvar had said - ‘Urruvar Ulgattaark AaniyaTattraad, Erru-vaare Ellaam Porutt’ That is, “Like a linchpin of an axle, a farmer holds together the entire world. He bears the burden of those people who cannot cultivate land.”

Our country is indebted to our farmers who are our annadata, because of whose hard work we are self-reliant in foodgrain. Bringing about a change in the lives of farmers who serve the country selflessly and development of rural areas, are the priorities of my Government. The Government is going to spend an amount of Rs 25 lakh crore in the coming years to strengthen the rural economy. Government is working on a strategy to develop an income centric system aimed at doubling the income of farmers.

Honourable Members, under the Prime Minister Kisan Samman Nidhi, more than Rs 43 thousand crore has been deposited in the bank accounts of more than 8 crore farmer families. On 2nd January this month, my Government has created a record by transferring Rs 12 thousand crore to the bank accounts of 6 crore farmers simultaneously.

My Government is working with dedication to provide the farmers, prices which are one and a half times the input cost. Steady increase in **MSP** for Kharif and Rabi crops is a step in this direction. Due to the efforts of the Government the procurement of pulses and oilseeds has increased by more than 20 times.

Honourable Members, my Government is also promoting alternative farming practices. Along with cluster-based horticulture,

organic farming is also being promoted and propagated. The production of honey has increased by about 60 per cent due to the efforts made by the Government in this area. The export of honey has also more than doubled. In order to build further on this accomplishment, the National Bee- Keeping and Honey Mission has been approved.

The twin objectives of doubling the fishermen's income and fish production are sought to be achieved through the newly created Department of Fisheries. A massive drive is being organized with the aim of ensuring the health of more than 50 crore livestock of the country. Under the National Animal Disease Control Programme, an amount of Rs 13 thousand crore is being spent on immunization and other measures to protect the cattle from **Foot and Mouth Disease**.

Honourable Members, my Government along with the State Governments is working with sensitivity to provide relief to farmers from natural calamities. Under the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, on an average, every year, more than five and a half crore farmers are availing crop insurance cover at a very low premium. Under this scheme in the last three years, claims of farmers to the tune of Rs 57 thousand crore have been settled.

The impact of **e-NAM**, the online national market for farmers has also started becoming visible. 1 crore 65 lakh farmers and about 1 lakh 25 thousand traders of the country have been linked to it. About Rs 90 thousand crore worth of business has been transacted through this platform. In order to further enhance the effectiveness of **e-NAM** in this decade, work is underway to link more than 400 new mandis with it.

Honourable Members, The health of an individual has impact on the development of both the family and the country. My Government is

working with a holistic approach in the area of health. Serious efforts are being made at every level in preventive and curative healthcare. Many schemes such as the Swachh Bharat Abhiyan, Jal Jeevan Mission, Poshan Abhiyan, Fit India Movement, Ayushman Bharat Yojana, are contributing to improving the health of the people.

The wide ranging impact of the Ayushman Bharat Scheme on the health sector of the country is visible. Under the Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, so far 75 lakh poor have availed free treatment. More than 27 thousand Health and Wellness Centres have also been set up.

Honourable Members, due to the decisions taken by my Government, medical expenses of the poor and the middle class have been reduced considerably. Capping of prices of more than 1000 essential medicines has resulted in a saving of Rs 12,500 crore for the patients. Reduced cost of stents and knee-implants has provided huge relief to lakhs of patients. Every day 5 to 7 lakh patients are now purchasing medicines for serious ailments at affordable prices from more than 6,000 Jan Aushadhi Kendras.

By setting up the National Medical Commission, my Government has reaffirmed its commitment to reform medical education and healthcare. 75 new medical colleges have been sanctioned this year, which will result in an increase in **MBBS** seats by about 16 thousand and **PG** seats by more than 4 thousand. In addition, 22 **AIIMS** have been sanctioned for various parts of the country, construction work for which is in progress.

My Government is also making special efforts to improve the health of women. Under the Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana, about Rs 5 thousand crore has been transferred by the Government

directly to the bank accounts of 1 crore 20 lakh women of the country. Under Mission Indradhanush, 3 crore 50 lakh infants and about 90 lakh pregnant women have been vaccinated. Benefits of these schemes are particularly visible in areas inhabited by dalits and tribals. My Government has also started making oxo-biodegradable sanitary napkins 'Suvidha' available for just one rupee.

Honourable Members, because of the efforts of my Government to promote entrepreneurship and livelihood for women, more than 6 crore 60 lakh women have already joined the Self Help Group movement. These women are being provided credit at low interest rates. In order to provide equal opportunities, for the first time women have been allowed to work during the night shift also in both under-ground and open cast mines. It is with this same objective of promoting gender equality that admission of girls has been permitted in Sainik Schools for the first time. Appointment of women in the Military Police is also underway. For the first time the Indian Air Force is providing new opportunities for women to work in the fighter stream and as defence attachés.

Honourable Members, my Government is working with sensitivity for ensuring the safety of women. In order to enhance women's safety, more than 600 One Stop Centers have been set up in the country. A national database has been created to identify the perpetrators of crimes against women. More than 1 thousand Fast Track Special Courts will be set up across the country to ensure speedy justice in such cases. It has also been decided to set up a **Women Help Desk** in every police station of the country. For heinous crimes like sexual offence against children, Government has made a provision even for capital punishment.

Honourable Members, the 21st century is referred to as the Century of Knowledge and the priority of the Government is to prepare the youth to provide leadership in this field. In the areas related to Research, Innovation, Incubation and Start-Ups, it is the youth who will be at the forefront in this decade. The youth are benefitting continuously from the policy decisions taken by my Government in this regard. Today, India is home to the world's third largest start-up ecosystem. Under the Start-Up India campaign, recognition has been accorded to 27 thousand new start-ups in the country. The number of patents granted in the country has increased four times in the last five years, whereas trademark registrations have increased five-fold.

Through the Skill India Mission and National Apprenticeship Promotion Scheme, along with skill development the youth are also being provided with necessary funds for self-employment. More than 5 crore 54 lakh new entrepreneurs in the country have availed loans under the Mudra scheme. So far, credit in excess of Rs 10 lakh crore has been sanctioned under this scheme.

Honourable Members, my Government is laying emphasis on schemes aimed at improving quality of education and promoting **innovation**. More than Rs 37 thousand crore has been sanctioned for modernization of 75 educational institutions in the country through the **Higher Education Funding Agency (HEFA)**. Government has initiated action for appointment of about 7 thousand teachers in Kendriya Vidyalayas and 12 thousand teachers in Higher Education Institutions. 'Swayam2' has also been introduced by the Government to strengthen the online education system.

I am delighted to inform you that for the first time ever in the history of the country, number of girls admitted in higher education has

exceeded that of boys.

Honourable Members, our youth have the potential to transform India into a great sporting power in the world. Under various schemes, including the Khelo India programme and the Olympic Podium Scheme, young talent is being identified and provided with requisite training to compete at the highest level. The third phase of Khelo India programme has been successfully concluded in Guwahati just a few days back. It is worth noting that 80 new national records were set there, of which 56 were set by women.

Honourable Members, this year 1st August marks the hundredth death anniversary of the great freedom fighter, Bal Gangadhar Tilak, who had given the clarion call that Swaraj is our birth right. After attainment of Swaraj, the nation has now started moving towards Suraaj. Moving rapidly towards the goal of Suraaj, my Government is working at three levels:

- First – Transforming the work culture in Government and strengthening institutions,
- Second - Use of modern technology to promote transparency,
- And third - promoting healthy competition and public participation at the grassroot level.

Honourable Members, following the fundamental principle of “**Minimum Government, Maximum Governance**”, several reforms have been undertaken by the Government. With its recent abolition of **58** more laws, the number of laws abolished by the Government has now reached about **1500**. **Reforms** in recruitment process for every level are underway in order to promote transparency. The youth are benefitting

from the decision to discontinue interviews for most of the Group B posts and Group C posts.

Honourable Members, coordination among Departments and dismantling of **silos** are absolutely essential for successful implementation of schemes. In this direction, organization of a common Foundation Course for officers of more than 20 Civil Services in October last year is an important step. Recently, the management of Indian Railways has also been restructured. To make the functioning of various Tribunals in the country more effective, the Tribunal system too is being reformed. New Ministries have also been created to facilitate better target orientation of schemes. Creation of the Ministry of Skill Development and the Ministry of Jal Shakti by the Government is an example of this thought process.

Honourable Members, fast and accurate delivery of Government services and benefits has been the hallmark of my Government. This has been made possible by application of technology as a basis of good governance on an unprecedented scale. Identification of beneficiaries in a transparent manner, transfer of 100 per cent assistance directly to bank accounts of beneficiaries and use of modern technology in monitoring of schemes have made the lives of the poor and the middle class easier. This technology will also help in improving the quality of life of our countrymen during this decade.

Honourable Members, we are all aware that digital technology is the foundation of the Industrial Revolution **Industry 4.0**. My Government has focused on **Digital Access, Digital Inclusion** and **Digital Empowerment** in an unparalleled manner through the Digital India Programme in order to take full advantage of the Industrial

Revolution in the 21st century. It is a matter of pride for the country that digital systems developed in India during the last five years have been a source of inspiration for several countries of the world.

Honourable Members, today, more than 121 crore people in the country have Aadhaar cards and about 60 crore people possess **RuPay** cards. A record value of Rs 2 lakh crore has been transacted through **UPI** in December 2019. Recently, the Government has also launched a new version of the **BHIM App**.

The Government has linked about 450 schemes to Direct Benefit Transfer or **DBT** by using the **JAM** Trinity of Jan-Dhan, Aadhaar and Mobile. An amount of over Rs 9 lakh crore has been directly transferred to the bank accounts of the beneficiaries through **DBT**, during the last 5 years. By plugging the leakages, my Government has saved about Rs 1 lakh 70 thousand crore from going into the wrong hands.

The Government e-Marketplace, **GeM** has brought about transparency in Government procurement. **GeM** has not only opened up a huge market, in the form of the Government, for the small and micro entrepreneurs, it has also connected the Government directly with the entrepreneurs. During the last three years, about Rs 40 thousand crore worth of procurement has been done by different Government Departments through **GeM**.

By leveraging technology, my Government has taken several major steps to end the Inspector Raj. Now we are also developing a system in the Income Tax Department which would be devoid of any human interface. This system will increase transparency and improve work culture in the tax department.

Honourable Members, technology plays a major role in bringing cities and villages closer. So far, more than 1 lakh 25 thousand Gram Panchayats have been connected with high speed broadband under the BharatNet scheme. In 2014, there were 60 thousand Common Service Centres in rural areas of the country, which have now increased to more than 3 lakh 65 thousand. This has provided employment to more than 12 lakh villagers. Through these centres, the Government is delivering more than 45 services in rural areas.

Honourable Members, in order to strengthen the spirit of Ek Bharat, Shreshtha Bharat, My Government is developing integrated and organized systems for the countrymen, through use of technology.

Recently, **One Nation, One FasTag** has been launched to ensure **seamless mobility** in the country. **One Nation One Mobility Card** has enabled use of the same card for different modes of transport across different States. **One Nation, One Ration Card** is also being launched by the Government. **One Nation, One Tax**, that is **GST**, has also promoted transparency in trade and commerce through use of technology. In the pre **GST** period, more than two dozen different taxes had to be paid. Now, not only the complex tax web has come to an end, the incidence of tax has also been reduced.

Honourable Members, in a federal country like India it is imperative for fast paced development, that States compete with each other in development schemes; and also share experiences with each other. My Government has therefore been consistently emphasizing **Competitive Cooperative Federalism**. The Government is ranking States on the basis of **real time data** collected at district and village level. Its impact is visible in various areas ranging from Swachh Bharat

Abhiyan to Ease of Doing Business and Smart City Mission to Aspirational District Programme.

Information collected during the **Census** plays a crucial role in enabling Governments in formulation of appropriate schemes and targeted interventions. This time digital technology is being used, in the conduct of **Census**, to collect information so as to complete the process expeditiously.

My Government is committed to protecting privacy amidst the increasing use of digital technology. To fulfil this commitment, Government has introduced the **Data Protection Bill** in the Parliament.

Honourable Members, my Government is committed to attaining the goal of making India a USD 5 trillion economy. Towards this objective, Government is making efforts at all levels of the economy, in consultation with all stakeholders. In spite of global challenges, the fundamentals of Indian economy are strong. Our foreign exchange reserves have reached a historical high of over USD 450 billion. Inflow of **Foreign Direct Investment** to India is also on the rise. As compared to last year, **FDI** has increased by USD 3 billion between April and October this year.

On the other hand, merger of small Public Sector Banks has strengthened them and improved their lending capacity. In the first half of this financial year, 12 Public Sector Banks have reported profits. Due to the **Insolvency and Bankruptcy Code**, nearly Rs 3.5 lakh crores have also been recovered by the banks and other institutions. Reduction of corporate tax and the codification of Labour Laws will increase ease of doing business in India.

Honourable Members, my Government is providing impetus to Make in India to accelerate the growth rate of the economy and to boost manufacturing and exports. Government is developing two defence corridors in Tamil Nadu and Uttar Pradesh, in addition to 5 Industrial Corridors in the country.

Honourable Members, India is making rapid strides in electronics manufacturing sector in particular. National Policy on Electronics has been formulated to give further impetus to the manufacturing of mobile phones, TVs and other electronic devices. The value of electronic equipment manufactured in the country has increased to Rs 4 lakh 58 thousand crore in 2018-19, as against Rs 1 lakh 90 thousand crore in 2014-15. In 2014, there were only 2 companies manufacturing mobiles in India. Today India is the second largest mobile manufacturing hub in the world. Make in India is also being encouraged by the Government in automobile sector and railways. Full indigenous manufacturing of modern trains like Vande Bharat and Tejas Express is in progress.

Honourable Members, the fundamental mantra of independence was a Self-reliant India. A self-reliant India is possible only when every Indian takes pride in every product made in India. My Government believes in the mantra of '**Buy local for a better tomorrow**'. I urge every representative of the people, from Panchayat level to the Parliament, and every Government in the country, to transform the philosophy of 'Buy local for a better tomorrow' into a movement. I also urge every Indian to give priority to local products. By using locally manufactured products, you will be able to help the small entrepreneurs in your area to a great extent.

Honourable Members, the poor and the middle classes hope and aspire for a modern 21st century infrastructure in the country. To fulfil this aspiration of the people more than Rs 100 lakh crore will be invested in the next five years. With a special emphasis on connectivity, the Government is also focusing on creation of new highways, new waterways, new airways, and new I-ways.

Rural roads contribute significantly to the country's infrastructure. Rural roads have now been expanded to every corner of the country through the Pradhan Mantri Gramin Sadak Yojana. Third phase of the programme has been launched to strengthen rural roads and connect them to schools, hospitals and agricultural markets. 1 lakh 25 thousand kilometers of roads will be constructed and upgraded under this programme.

Inland waterways are also being developed by the Government. In December 2019, for the first time, container cargo reached Pandu in Assam via National Water Way-2. Under the Jal Marg Vikas Project, the multi-modal terminal at Haldia on River Ganga and the navigation lock at Farakka will be completed this year. It is also our endeavour to operate large transport cargo vessels on River Ganga by next year.

Rapid progress is being made towards providing better public transport facilities in urban areas. Metro facility has now been extended to 18 cities in the country. So far, 670 km of metro lines have been operationalized, and work on another 930 km is underway. The residents of Delhi and NCR have greatly benefitted from the construction of Delhi-Meerut Expressway, as well as from Eastern and Western Peripheral Expressways.

Honourable Members, Tier-2 and Tier-3 cities of the country are emerging in a new role towards achieving the goal of USD 5 trillion economy. The progress of small cities in areas relating to sanitation, amenities, start-ups or other commercial activities has been encouraging. Since 2014, start-ups in small cities have grown at a rate of 45 to 50 per cent. Similarly, about 35 lakh people have so far travelled by air under the UDAN scheme. Last year, 335 new air routes have been approved. It is estimated that in the coming years, more than half of the country's digital transactions will take place in these tier-2 and tier-3 cities.

My Government is doing its utmost to fulfil the developmental aspirations of small cities and the new middle class. The middle class in small towns has also benefitted the most from tax exemption on income up to Rs. 5 lakhs. The middle class families with annual income of up to Rs 18 lakhs are able to save between Rs 5 to 6 lakh on home loans with tenure up to 20 years. It is the middle class that will benefit the most from the Rs 25 thousand crore fund provided by the Government for completion of stalled housing projects.

Honourable Members, India is playing an effective role globally in the field of **clean energy**. Due to the efforts of the Government, LPG coverage in the country has increased from 55 per cent to about 97 per cent. City gas distribution is now being extended to **407** districts of the country. Now we are moving towards a **gas-based** economy.

Keeping environment conservation in mind, my Government has enhanced the target for producing renewable energy to 450 gigawatts. Under the Pradhan Mantri-Kusum Yojana, it has been targeted to provide more than 17 lakh solar pumps to farmers across the country.

Similarly, under the second phase of the solar roof top programme, the target is to generate 38 gigawatt of electricity.

Honourable Members, the efforts of the countrymen have made it possible to expand India's tree and forest cover by 13 thousand square kilometers during the last four years. Similarly, the number of tigers has increased to 2,967 in July 2019 from 2,226 in 2014, which is a matter of satisfaction.

To address the issue of air and water pollution, the Government will be implementing the National Clean Air Programme in 102 cities of the country. I am glad that the positive impact of the Namami Gange Mission launched by the Government has now started becoming visible. Under this mission, projects worth Rs 7 thousand crore have been completed and projects worth more than Rs 21 thousand crore are in progress.

The impact of all these efforts is also visible on the country's tourism sector. During the last few years, there has been extraordinary development of infrastructure related to tourism. Recently a nationwide programme has been launched from Kolkata for conservation and beautification of the heritage buildings of the country. The tourism sector is also being strengthened by the modern infrastructure being developed under Swadesh Darshan and PRASAD schemes. New records are being created every day in the number of tourists visiting the 'Statue of Unity', the statue of Sardar Patel; which is the tallest in the world.

Honourable Members, It is the belief of my Government that paying tribute to the great personalities who dedicated their lives to the nation and contributed towards preserving the heritage of the country is an important part of nation building. With this idea, museums

celebrating the contributions made by the brave tribals, both men and women, during our freedom struggle are being set up in different States. The 250th birth anniversary of the great social reformer Raja Ram Mohan Roy, whose teachings guided the nation, will also be celebrated in 2022 by the Government in a befitting manner.

Honourable Members, the objective of India's space programme has always been service to humanity. Due to the tireless work of country's space scientists, Chandrayaan-2 has stimulated a new interest in technology among the country's youth. My Government has already approved Chandrayaan-3. **ISRO** is also working expeditiously on the manned spacecraft programme – Gaganyaan, as well as Aditya-1 Mission.

Honourable Members, in these evolving times, to meet the new and complex challenges related to the defence of the country, my Government is working to make the defence forces stronger, more effective and modern. The appointment of **CDS**, the **Chief of Defence Staff** and creation of the **Department of Military Affairs** are steps in this direction. This will also improve coordination among the three services, while speeding up their modernization and the process of making them self-reliant.

We are fully attentive to the requirements of our security forces, including adequate armaments, safety equipment and bullet proof jackets. Manufacture of state-of-the-art **AK 203** rifles, in collaboration with Russia, will commence in the Ordnance Factory at Amethi in Uttar Pradesh. Recently, when the **Naval Prototype** of Tejas landed and took off from **INS Vikramaditya**, every Indian was filled with pride. The Government has also taken historic steps in enhancing space security.

With the successful testing of **A-Sat**, India has become the fourth country in the world to attain strike capability in space.

Honourable Members, my Government is working with full strength and determination to free the country from the scourge of terrorism. In view of the changing nature of terrorism, alertness on the part of the citizens is extremely helpful. The decrease in terrorist activities in Jammu Kashmir demonstrates that public cooperation can be effective in the fight against terrorism. My Government has given the security forces a free hand in taking the strongest measures against those indulging in terrorism. The security situation in the North East has also improved significantly due to the concerted efforts of the Government. The geographical spread of Naxalism is also steadily shrinking.

Honourable Members, my Government is of the view that foreign policy is a vital ingredient of the country's economic and strategic security. We are stimulating economic growth and prosperity by increasing connectivity with our neighbouring countries. **"Neighbourhood First"** policy is our priority. Apart from our neighbours, we have also strengthened relations with other countries of the world. This is why a number of countries have bestowed their highest honour on India. Our cooperation with ASEAN and African countries is being taken to a new level.

After International Solar Alliance, India has been at the forefront of a global partnership, **Coalition on Disaster Resilient Infrastructure-CDRI**. This step aimed at mitigating natural disasters will further strengthen India's stature as a sensitive world power.

Honourable Members, this decade, which has just begun, will determine India's global standing in the times to come. The world will

witness an inclusive, prosperous, capable and powerful New India in this decade. Hence it is the bounden duty of every Member of this House and every countryman to strive hard with all their capability to achieve their respective goals.

We should all strive to make every citizen conscious of and dedicated to his duties in the national interest, and ensure that this sense of responsibility becomes the guiding principle of our civic life. Come, let us together make this decade of 2020 the decade of fulfilling our duties.

We must always remember that we are first and foremost citizens of this country, and leaders or supporters of a particular ideology thereafter. The prestige of our country should be more important than our party loyalties.

It is my belief that in the times to come, all of us together, drawing inspiration from the glorious past of our country, will make every possible effort to ensure a bright future for the country; and that we will also succeed in our endeavour.

Let us all come together to fulfil the dream of a New India; let us together make a New India.

Jai Hind !!!